रिज़र्व बैंक ने बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना का स्वागत किया

एक अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग, और सामान्य रूप से, वित्तीय मध्यस्थता, प्रणाली स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। आर्थिक इतिहास ने हमें बार-बार दिखाया है कि यह स्वस्थ फर्मों और उधारकर्ताओं को उधार देने वाले स्वस्थ बैंक हैं जो निवेश और नौकरी सृजन के एक अच्छे चक्र का निर्माण करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत सरकार का निर्णायक पैकेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मद्देनजर देश के आर्थिक भविष्य की सुरक्षा में एक अगला महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दशक में पहली बार, बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक और सुसंगत रणनीति के लिए अब हमारे पास एक वास्तविक मौका है कि जब टुकड़ों में बटे भोजन के बजाय जिग्सॉ पहेली के सभी नीतिगत टुकड़े उपलब्ध हैं। इससे हमें अच्छा शकुन मिलता है कि स्वस्थ समष्टि-आर्थिक स्थिति के समय में अर्थव्यवस्था के लिए अन्य मोर्चों पर उठाया गया यह एक कदम है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पूनर्पूंजीकरण पैकेज में अनेक वांछनीय विशेषताएं संयुक्त की गई हैं। पहला, पुनर्पूंजीकरण बॉन्डों का उपयोग करके, जबकि कुछ समय से संबंधित राजकोषीय प्रभाव के लड़खड़ाते रहने के बावजूद इससे शुरू में पूंजी प्रणाली में आएगी।पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड ब्याज व्यय को छोड़कर सरकार के लिए चलनिधि तटस्थ होंगे जो कि वार्षिक राजकोषीय घाटे में योगदान देंगे। दूसरा, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजी शेयरधारकों की सहभागिता शामिल होगी जिसके लिए पूंजी के कुछ भाग को बाजार वित्तपोषण के माध्यम से पूरा किए जाने की आवश्यकता होगी। अंतिम किंतु जिसका महत्व कम नहीं है, इससे कैलिब्रेटिड दृष्टिकोण होगा जिसमें वे बैंक जिन्होंने अपने तुलन-पत्र मुद्दों को बेहतर ढ़ंग से सुलझा लिया है और तत्काल क्रेडिट सृजन के लिए नए सिरे से डाली गई पूंजी का उपयोग करने की स्थिति में हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि अन्यों को ऐसी ही स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें पहले के पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रमों की तुलना में सार्वजनिक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम में कुछ बाजार अनुशासन लाने के लिए सही तरीके का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय बाजार नीतियों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए वृद्धि में सहयोग देना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, मैं इस दिशा में सरकार के साहसिक कदम की प्रशंसा करता हूं, जहां शुरुआत में शोध-अक्षमता और दिवालिया कोड को लागू किया गया जो अंतर्निहित कॉर्पोरेट दबाव का समाधान करने में सहायता कर रहा है और जिसका चरमोत्कर्ष कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूनर्पूंजीकरण कार्यक्रम की घोषणा के रूप में हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए इन योजनाओं को उनके प्राकृतिक संपूर्णता पर पहुंचाने के लिए सरकार के साथ कार्य करेगा।

(उर्जित आर. पटेल)
गवर्नर